दैनिक जागरण
सफलता एक प्रतिशत भाग्य और 99 प्रतिशत परिश्रम का परिणाम है

कांग्रेस का आत्ममंथन

इन दिनों देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस में क्या हो रहा है और वह किधर जा रही है, यह शायद कोई भी और यहां तक कि कांग्रेसी नेता भी नहीं जानते। इस पर हैरान ही हुआ जा सकता है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों की घोषणा होने के चंद दिन बाद राहुल गांधी विदेश यात्रा पर चले गए। पता नहीं राहुल इन राज्यों में चुनाव प्रचार करने जाएंगे या नहीं, लेकिन ऐन मौके पर उनके विदेश जाने से आम कार्यकर्ताओं के बीच तो यही संदेश गया कि वह इन चुनावों को महत्व नहीं दे रहे हैं। भले ही सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर फैसले करने में लगी हुई हों, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि वह अपने नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और उन्हें दिशा दिखाने की जरूरत समझ रही हैं। वास्तव में इसी कारण पार्टी के नेता एक ही मसले पर अलग-अलग बयान देने में लगे हुए हैं। वे एक-दूसरे की सार्वजनिक तौर पर आलोचना भी करने में लगे हुए हैं। इससे भी खराब बात यह है कि वे राष्ट्रीय महत्व के मसलों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सतही मसलों पर जुमलेबाजी करने में लगे हुए हैं।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के इस बयान से शायद ही कोई असहमत हो कि कठिन दौर से गुजर रही पार्टी अपना भविष्य तय नहीं कर सकती। यदि उन्हें हरियाणा और महाराष्ट्र में पार्टी के जीतने की संभावना नहीं दिख रही है तो यह सच की स्वीकारोक्ति ही है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पार्टी अभी तक हार के कारणों पर गौर नहीं कर सकी है। यह अजीब है कि लोकसभा चुनाव नतीजे आने के चार माह बाद भी कांग्रेस ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि उसे एक और करारी हार का सामना क्यों करना पड़ा? यह तो वह काम है जो प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए था। सलमान खुर्शीद के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इसमें कोई दोराय नहीं कि पार्टी को आत्ममंथन करने की जरूरत है। इस तरह की बातें अन्य अनेक नेताओं की ओर से भी की जा चुकी हैं। कोई नहीं जानता कि इस जरूरत की पूर्ति क्यों नहीं हो रही है? आखिर यह क्यों न माना जाए कि कांग्रेस जानबूझकर आत्ममंथन से बच रही है? सच जो भी हो, लोकसभा चुनावों में 11 करोड़ से अधिक वोट पाने और चार प्रमुख राज्यों में शासन करने वाली कांग्रेस अपनी दयनीय दशा से उबरने की कोशिश न करके केवल अपना ही नहीं, भारतीय लोकतंत्र का भी अहित करने में लगी हुई है।

विसर्जन पर हो विचार

हमारे देश में दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा, विश्वकर्मा पूजा से लेकर कई और पूजाएं होती हैं जिसमें प्रतिमा की पूजा की जाती है और संपन्न होने के बाद उसे विभिन्न नदियों में विसर्जित किया जाता है। खासकर बंगाल में तो पतित पावनी गंगा (हुगली) नदी में भारी संख्या में प्रतिमाओं का हर वर्ष विसर्जन होता है। जिससे गंगा में प्रदूषण की मात्रा और बढ़ जाती है। ऐसे में अब दुर्गा प्रतिमा हो या फिर काली प्रतिमा इन सबके गंगा में विसर्जन को लेकर लोगों को विचार करने की जरूरत है। हालांकि कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने बंगाल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार समेत 11 राज्यों को 15 सूत्रीय दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें सबसे अहम है कि गंगा नदी और इसकी सहायक नदियों में प्रतिमा विसर्जन पर रोक लगाना। इस पर रोक के लिए अब 50 हजार रुपये का जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। परंतु देखा जा रहा है कि मंगलवार से जब दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन शुरू हुआ तो हजारों की संख्या में प्रतिमाओं को गंगा नदी में विसर्जित किया गया। मां दुर्गा को विसर्जित करने में लोग यह भूल गए कि वे एक और मां यानी गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं। प्रतिमा को रंगने को जिन रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें शीशा और अन्य रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल होता है और वह सब प्रतिमा से साथ गंगा के जल में मिल कर उसे प्रदूषित कर देते हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से स्थानीय निकायों की ओर से विसर्जन के साथ ही प्रतिमाओं को बाहर निकालने की व्यवस्था की गई है, लेकिन गंगा में प्रदूषण नहीं रुक रहा है। इसकी वजह है कि मिट्टी से बनी प्रतिमाएं पानी में डूबने के साथ ही तुरंत घुलने लगती हैं और रंग जल में मिल जाता है। गंगा की सफाई से जुड़ी संस्थाओं ने गंगा को प्रदूषित होने से बचाने को लेकर महानगर समेत राज्यभर में पूजा आयोजकों से इस विषय पर विस्तार से चर्चा की, ताकि गंगा को प्रदूषण से बचाया जा सके। परंतु देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार की सख्ती और राज्य के स्थानीय निकायों की तत्परता के बावजूद स्थिति नहीं बदल रही है। हालांकि कुछ ऐसे पूजा आयोजक हैं जिन्होंने इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किया। परंतु अधिकांश ने नहीं। इस पर सिर्फ सरकारी कार्रवाई या निर्देश से कुछ नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक है कि हर व्यक्ति को गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए आगे आना होगा।

> मां दुर्गा को विसर्जित करने में लोग यह भूल गए कि वे एक और मां यानी गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं

चीन को जरूरी संदेश देने का समय

विवेक काटजू

भारत व्यापार एवं निवेश सहित तमाम क्षेत्रों में चीन के साथ सहयोग करना चाहता है, लेकिन यह एकतरफा नहीं हो सकता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दूसरी अनौपचारिक वार्ता के लिए चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग भारत आ रहे हैं। दोनों नेता 11-12 अक्टूबर को तमिलनाडु के मामल्लापुरम में मिलेंगे। दोनों के बीच ऐसी पहली वार्ता गत वर्ष अप्रैल में चीन के वुहान में हुई थी। इन बैठकों का मकसद यही है कि दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बहुत सहज माहौल में स्पष्टता के साथ विचारों का आदान-प्रदान हो। यह उम्मीद जताई गई कि इससे मैत्री भाव बढ़ेगा और द्विपक्षीय रिश्तों की राह सुगम होगी। नेताओं के बीच मित्रता भाव रिश्ते बेहतर बनाने में मददगार होता है, लेकिन इसकी एक सीमा है, क्योंकि देशों की नीतियां हमेशा राष्ट्रीय हितों एवं राष्ट्रीय आकांक्षाओं से निर्धारित होती हैं। यह बात भारत-चीन संबंधों पर भी लागू होती है। महज 40 वर्षों से भी कम अवधि में चीन एक वैश्विक शक्ति बन गया है। वह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सैन्य मोर्चे पर बड़ी ताकत बनने के बाद वह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी तेजी से तरक्की कर रहा है। उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं और वह आक्रामक रूप से अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी और दक्षिण एशिया में उसका दखल खास तौर पर बढ़ा है। चीन अपना वर्चस्व भारत सहित तमाम महत्वपूर्ण एशियाई देशों की कीमत पर बढ़ा रहा है।

वर्ष 1988 में राजीव गांधी के चीन दौरे के बाद से सभी भारतीय सरकारों ने चीन के साथ कई क्षेत्रों में मेलजोल बढ़ाने की हरसंभव कोशिश की। हालांकि दोनों देशों के बीच कुछ मुद्दों पर टकराव को देखते हुए इनमें एहतियात भी बरती गई। यह रणनीति एकदम सही रही, लेकिन इससे भारत-चीन के मतभेद दूर नहीं हुए। चीन ने भारतीय हितों को लेकर अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई। चीन के रवैये से यही जाहिर होता रहा कि वह भारतीय हितों की अनदेखी करता है। हाल में जम्मू-कश्मीर में मोदी सरकार के संवैधानिक कदम पर उसकी प्रतिक्रिया से फिर इसकी पुष्टि हुई। भारत द्वारा यह समझाने के बावजूद चीन ने विरोध दर्ज कराया कि अनुच्छेद 370 हटाने से पाक के साथ नियंत्रण रेखा या चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। चीन ने जम्मू-कश्मीर में बदले घटनाक्रम को लेकर दुनिया भर में भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तान से ही सहानुभूति जताई। पाकिस्तान की मनुहार पर चीन इस मसले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अनौपचारिक बैठक में भी ले गया जहां उसने भारत विरोधी रुख अपनाया। बैठक के बाद बयान जारी करने की उसकी मंशा पर अन्य सदस्यों ने पानी फेर दिया। इसके बाद चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू-कश्मीर का उल्लेख करते हुए कहा कि यह मसला संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र, सुरक्षा परिषद प्रस्तावों और द्विपक्षीय समझौतों के अनुरूप सुलझाया जाना चाहिए। चीन का रवैया पाकिस्तान के लिए मददगार रहा, क्योंकि सुरक्षा परिषद में जम्मू-कश्मीर के मसले पर चर्चा कब की इतिहास के पन्नों में दफन हो चुकी थी। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि चीन और पाकिस्तान की साठगांठ 1962 से चली आ रही है। इसी दुरभिसंधि के दम पर पाकिस्तान भारत को लगातार आंखें दिखाता रहा। उसके तेवर अब और ज्यादा तीखे हो रहे हैं। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के चलते उसे नया संबल मिला है। भारत ने इसका उचित ही विरोध किया है कि यह भारतीय संप्रभुता का उल्लंघन करने वाली परियोजना है। चीन ने कभी भी पाकिस्तान पर आतंकवाद को खत्म करने के लिए दबाव नहीं डाला। जैशे मुहम्मद के सरगना मसूद अजहर को अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कराने की मुहिम को उसने तभी समर्थन दिया जब अमेरिका ने उसे सुरक्षा परिषद में बेनकाब करने की धमकी दी।

अवधेश राजपूत

चीनी राष्ट्रपति के भारत दौरे से ठीक पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख जनरल कमर बाजवा ने चीन का दौरा किया। यह दौरा इसी मंशा से किया गया कि भारत-चीन संबंधों में सुधार चीन-पाकिस्तान संबंधों की कीमत पर नहीं हो। यह भी महत्वपूर्ण है कि इमरान खान ने कश्मीर के संदर्भ में दक्षिण एशिया में शांति एवं सुरक्षा पर चर्चा का प्रस्ताव रखा। भारत इसकी अनदेखी नहीं कर सकता। उसे चीन को बताना होगा कि अपने हितों की रक्षा के लिए जो जरूरी कदम होंगे, उन्हें उठाने से वह हिचकेगा नहीं। अरुणाचल में हिम विजय सैन्य अभ्यास से यही संदेश गया।

पाकिस्तान के साथ-साथ चीन ने सभी दक्षिण एशियाई देशों में अपनी सक्रियता बढ़ाई है। इसके लिए वह अपने विशाल वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है। भारत की सुरक्षा के लिए इनके गहरे निहितार्थ हैं। भारत आर्थिक मोर्चे पर चीन की बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन वह अपने पड़ोसियों के समक्ष यह पेशकश तो कर ही सकता है कि वे भी भारत की तरक्की के साथ प्रगति करें। इसके लिए आदर्श परस्पर भाव विकसित करना होगा। इस जुड़ाव से पड़ोसी देश भी चीन के साथ करार करते हुए भारत के सुरक्षा हितों को लेकर सचेत रहेंगे। मोदी सरकार यह रणनीति अपना तो रही है, पर अब इसे एक औपचारिक सिद्धांत के रूप में तब्दील करना होगा।

चीन हिंद महासागर के साथ ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी सक्रियता बढ़ा रहा है। यहां अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए भारत को सतर्क रणनीति अपनानी होगी। उसे अन्य देशों के साथ मिलकर मजबूत नेटवर्क बनाने होंगे। ये नेटवर्क इस क्षेत्र में सामरिक कड़ियों को सशक्त बनाएंगे। इसमें संदेह नहीं कि मामल्लापुरम में दोनों नेताओं के बीच व्यापार एवं निवेश पर गहन चर्चा होगी। चीन को अपनी अर्थव्यवस्था में भारत के लिए दवा जैसे उन क्षेत्रों में दरवाजे खोलने की प्रतिबद्धता दिखानी होगी जिनमें भारत मजबूत है। वह तरीका विशुद्ध औपनिवेशिक है जिसमें चीनी फैक्ट्रियां भारतीय कच्चे माल का उपभोग करती हैं और भारत चीनी उत्पादों का आयात करता है। यह सिलसिला कायम नहीं रखा जा सकता। भारत को 5-जी जैसी शक्तिशाली संवेदनशील तकनीक में चीनी कंपनियों को प्रवेश देने से पहले सावधानी से पड़ताल करनी चाहिए।

चीन को तीन जरूरी संदेश अवश्य समझने चाहिए। एक यह कि भारत उसके साथ संघर्ष नहीं चाहता, लेकिन अपने हितों की रक्षा से पीछे नहीं हटेगा। डोकलाम गतिरोध इसका सटीक उदाहरण है। दूसरा यह कि भारत व्यापार एवं निवेश सहित तमाम क्षेत्रों में चीन के साथ सहयोग करना चाहता है, लेकिन यह एकतरफा नहीं हो सकता और चीन को भारत की चिंताओं पर गौर करना होगा। तीसरा यह कि भारत उसके साथ सीमाओं का शांतिपूर्ण समाधान चाहता है और इस मामले में वह ज्यादा अड़ियल रुख न अपनाए। इसमें संदेह नहीं कि शी चिनफिंग के साथ वार्ता के दौरान ऐसे तमाम बिंदुओं पर मोदी मंथन जरूर करेंगे।

(लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं)

response@jagran.com

शिक्षित समाज की पोल खोलता सर्वेक्षण

एनके सिंह

यह शुभ संकेत नहीं कि संपन्न और शिक्षित लोग भी बच्चों के पोषण को लेकर सजग नहीं दिख रहे हैं

देश में पहली बार किए गए राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण ने शिशुओं और किशोरों के पोषण को लेकर जो रिपोर्ट जारी की है उस पर नीति-नियंताओं के साथ आम जनता को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह कई ऐसे तथ्य प्रकट करते हुए बताती है कि संपन्न और शिक्षित लोग भी बच्चों के पोषण को लेकर सजग नहीं। यह रिपोर्ट एक सर्वेक्षण का हिस्सा है। अपनी किस्म का यह पहला सर्वेक्षण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा 2016-18 काल खंड में किया गया। व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण का सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि देश में जन्में दो साल से कम के शिशुओं में मात्र 6.4 प्रतिशत सौभाग्यशाली हैं जिन्हें न्यूनतम स्वीकार्य पोषक आहार मिलता है। इससे भी चौंकाने वाला तथ्य यह है कि इस पैमाने पर जो राज्य सबसे निचले पायदान पर हैं वे आर्थिक, शैक्षिक और विकास के पैमानों पर दशकों से काफी ऊपर हैं। इस कारण समाजशास्त्रियों और सामाजिक-आर्थिक विश्लेषकों के समक्ष यह प्रश्न खड़ा हुआ है कि क्या आर्थिक संपन्नता के कारण अभिभावक बच्चों की उचित परवरिश को नजरअंदाज करने लगे हैं?

इस अवधारणा की पुष्टि इस बात से भी होती है कि जिन राज्यों में शिशु पोषण की स्थिति काफी बेहतर है उनमें से अधिकांश अविकसित कहे जाने वाले राज्य जैसे ओडिशा, छत्तीसगढ़ , झारखंड और असम हैं। केवल केरल एक अपवाद है, जबकि दशकों से पिछड़ेपन का दंश झेलने वाल राज्यों में पैदा होने वाले शिशुओं के पोषण की स्थिति राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर पाई गई। ये आंकड़े इसलिए गंभीर परिणाम की और इंगित करते हैं, क्योंकि अगर संपन्न राज्यों में शिशुओं की परवरिश ठीक नहीं है तो यह बच्चों के प्रति सोच, बाजारू ताकतों का खान-पान पर कुप्रभाव और अभिभावकों की संपन्नता-जनित व्यस्तता और उसकी वजह से लालन-पालन का काम सेवकों, आयाओं के भरोसे छोड़ने की मजबूरी की तस्वीर पेश करता है।

इसकी भयावहता तब और बढ़ जाती है जब यह सामना आता है कि आंध्र प्रदेश में मात्र 1.3 प्रतिशत शिशु पोषक तत्वों वाला भोजन पाते हैं, जबकि महाराष्ट्र में सिर्फ 2.2, गुजरात, तेलंगाना और कर्नाटक में मात्र 3.8 और तमिलनाडु में 4.2 प्रतिशत। इस पैमाने पर सबसे बेहतर राज्य सिक्किम है जहां 35.2 प्रतिशत शिशु समुचित पोषक तत्वों वाला भोजन पाते हैं, दूसरे नंबर पर केरल (32.6) प्रतिशत है। अर्थिक रूप से संपन्न वर्ग का हर

आठवां बच्चा स्थूल शरीर का पाया गया, जबकि देश के हर दसवें बच्चे में मुधुमेह-पूर्व के लक्षण मिले। इसका मतलब है कि उनमें मुधुमेह होने की प्रबल आशंका है। गरीबों में प्रत्येक सौ में से एक बच्चे में मोटापा पाया गया। रिपोर्ट के अनुसार आज भी देश का हर तीसरा बच्चा नाटा (स्टंटेड) है यानी उम्र से कम लंबाई वाला। इसी तरह लगभग हर तीसरा बच्चा उम्र के अनुसार कम वजन का है, जबकि हर छठवां बच्चा दुबले शरीर का यानी लंबाई के हिसाब से कम वजन का होता है।

संयुक्त राष्ट्र संगठन यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा के अनुसार उपरोक्त तीनों लक्षणों का मूल कारण बच्चों को समुचित और संतुलित आहार न देना है। इसकी वजह से बच्चों की बौद्धिक क्षमता कम हो जाती है। विशेषज्ञों की राय में किसी देश के नागरिकों की बौद्धिक-शारीरिक क्षमता कम होने के कारण वहां के सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट आती है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद ओलंपिक खेलों में खराब प्रदर्शन से भी इसे समझा जा सकता है। अपने देश में स्कूल जाने की आयु से पूर्व के हर पांच बच्चों में दो, स्कूल जाने वाले हर चार बच्चों में एक और तरुणवय वाले 28 प्रतिशत बच्चों में खून की कमी पाई गई। इन संगठनों के मानदंडों के तहत समुचित और संतुलित पोषण के लिए सात खाद्य पदार्थ रखे गए हैं। इनमें से क्षेत्र विशेष की पसंद के साथ किन्हीं चार को देकर शिशुओं का अच्छा पालन-पोषण कर सकते हैं। इनमें आलू, दाल, अंडा, मांसाहार, फलों का रस, स्थानीय सब्जियां और दूध से बने पदार्थ हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि संपन्न और शिक्षित वर्ग शायद विज्ञापनों से भ्रमित होकर इन सहज खाद्य पदार्थों की जगह जंक फूड जैसे चिप्स, नूडल्स, बर्गर देकर अपने अहंकार को संतुष्ट कर लेता है, बगैर यह सोचे कि वह बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहा है। तरुणवय में यानी 13-18 तक की आयु में खून की कमी और बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चे जंक फूड की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कामकाजी अभिभावकों को भी यह आसान लगता है, क्योंकि खाना-बनाने में व्यय होने वाले समय की बचत हो जाती है। स्वास्थ्य मानदंडों के अनुसार मां का दूध पीने वाले शिशुओं को कम से कम तीन बार अन्य पौष्टिक पदार्थ खिलाना चाहिए जबकि ऊपर का दूध पीने वाले शिशुओं को पांच बार। शायद कामकाजी अभिभावकों के लिए यह सब संभव नहीं होता।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य मिशन की ओर से 2015 में जारी पोषण संबंधी रिपोर्ट के बाद यह पहला राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन है। अब तक की रिपोर्टों से अलग इस अध्ययन की खास बात यह है कि शरीर की बौद्धिक और भौतिक क्षमता के लिए माइक्रो पोषक तत्वों के स्तर का आकलन इतने बड़े पैमाने पर (1.10 लाख बच्चों पर) पहली बार हुआ है। सरकार चाहती है कि 2022 तक कुपोषण से बच्चों को पूरी तरह छुटकारा दिलाया जाए, लेकिन मौजूदा रफ्तार से यह संभव नहीं लगता। समस्या यह है कि अगर कामकाजी अभिभावक बच्चों को बाजार के प्रभाव में चिप्स, नूडल्स, अन्य फास्ट फूड देंगे या फिर उन्हें घरेलू सेविकाओं के भरोसे छोड़ देंगें तो सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगी। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी मन की बात कार्यक्रम में कई बार देश के अभिभावकों को समुचित और संतुलित आहार देने की वकालत कर चुके हैं। उचित यह होगा कि गरीब तबके के साथ संपन्न तबका भी पोषण के महत्व को समझे। यह तभी हो सकता है कि जब जंक फूड के हानिकारक प्रभावों के बारे में जानकारी से लैस हुआ जाएगा।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

जीवन के सर्वोत्तम पल

जन्म के पल मनुष्य के जीवन के सर्वश्रेष्ठ पल होते हैं। सभी को उत्सुकता से उसके आने की प्रतीक्षा होती है। उसके जन्म लेने पर सभी को हर्ष होता है। उसके जन्म से पूर्व ही उसके भविष्य को लेकर कई सुनहरे सपने देख लिए जाते हैं। वह जैसे-जैसे बड़ा होता है, जीवन की कठोर वास्तविकता जुड़ती जाती हैं। आशाएं घटती जाती हैं। आशावादिता सुख का सबसे बड़ा स्रोत है। जब जीवन में आशा बलवती होती है तो मनुष्य का मन स्वयं भी प्रफुल्लित रहता है। उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। आशाओं से रहित मनुष्य भी कार्य करता है, किंतु उनमें प्रफुल्लता और रुचि का अभाव होता है। कार्य एक विवशता और कर्तव्य बन जाता है। ऐसे कार्यों से भले ही धन अर्जित कर लिया जाए, पद-प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, किंतु उल्लास नहीं उत्पन्न होता। आशाओं का संबंध अंतर्मन से है। आशाएं जब पूरी होती हैं, मन को संतुष्ट, संतृप्त करती हैं, जबकि धन, पद, शक्ति का अर्जन कामनाओं को उत्प्रेरित करता है और संवेग बढ़ाता है। मन को संतृप्त करने वाली आशाएं वास्तव में हैं क्या? मन तब प्रफुल्ल होता है जब वह स्थिर हो जाए, संतुष्ट हो जाए। ऐसा संचयन से नहीं अर्पण से होता है। लेना एक सांसारिक मनुष्य का चरित्र है, जबकि देना ईश्वरीय तत्व है। केवल ईश्वर ही है जो दे रहा है, युगों-युगों से दे रहा है। लेने, पाने की आशा, आशा नहीं कामना है। देना, कर्म नहीं आत्म संतुष्टि की आशा है।

जब मनुष्य आत्म संतुष्टि की आशा के साथ जीता है तो दया, क्षमा, उदारता, परोपकार, संयम और सहजता जैसे गुण स्वयं ही विकसित होने लगते हैं। किस कार्य से मनुष्य को आत्मतुष्टि मिल रही है यह उसे स्वयं ही समझना और तय करना होता है। वह जीवन में जो भी कार्य करे, इस विश्वास से करे कि यह उसे आत्मिक संतृप्ति प्रदान करने वाला है। जब यह भावना कार्य और जीवन का मुख्य उद्देश्य बन जाती है तो जीवन बदल जाता है। मनुष्य का हर भला कार्य उसे नया जन्म देने वाला सिद्ध होता है। वह अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा के साथ ही सुख का स्रोत भी बन जाता है।

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह

नासूर बनता मानसिक तनाव

सौरभ जैन

सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने वालों से लेकर बेरोजगार लोग तक तनाव की चपेट में आ रहे हैं

'यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो, कुछ तो उपयुक्त करो तन को नर हो, न निराश करो मन को' मैथिलीशरण गुप्त की ये पंक्तियां विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर प्रासंगिक हो जाती हैं और ऐसे समय में जब इसकी थीम आत्महत्या को रोकने पर हो तब इन शब्दों के अर्थ और व्यापक हो उठते हैं। वर्तमान जीवनशैली कुछ इस प्रकार हो गई है कि मानसिक तनाव एक आम बात हो गई है। सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण पदों पर कार्य करने वालों से लेकर बेरोजगार लोग तक इसकी चपेट में आ रहे हैं। दुनिया भर में अवसाद से प्रभावित लोगों की संख्या करीब 32.2 करोड़ आंकी गई है, इस आंकड़े का 50 फीसद लोग सिर्फ भारत और चीन से हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में अवसाद से ग्रसित लोगों की अनुमानित संख्या में वर्ष 2005 से 2015 के बीच 18.4 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2015 में 7.88 लाख लोगों ने आत्महत्या की और इससे कई गुना ज्यादा लोगों ने आत्महत्या का प्रयास किया। डब्ल्यूएचओ के इन आंकड़ों की मानें तो देश में कुल 6-7 फीसद लोगों को किसी ना किसी तरह की दिमागी समस्या है, जबकि 1-2 फीसद रोगियों को गंभीर समस्या है। अकेले भारत में 5 करोड़ से ज्यादा लोग अवसाद के शिकार हैं।

ऑनलाइन जर्नल लैंसेट पब्लिक हेल्थ की बीते वर्ष जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 में सर्वाधिक आत्महत्याएं भारत में हुई थीं। विश्वभर में 8,17,000 लोगों ने खुदकुशी की, जबकि भारत में यह संख्या 2,30,314 थी। इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में महिला और पुरुष दोनों में आत्महत्या से होने वाली मृत्यु की दर बढ़ रही है। आत्महत्या करने वाली प्रत्येक तीन महिलाओं में एक भारत से थी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार देशभर में साल 2014 से 2016 के बीच 26,476 छात्रों ने आत्महत्या की। इनमें 7,462 छात्रों ने आत्महत्या विभिन्न परीक्षा में फेल होने के डर से की। किसानों की आत्महत्या की अगर बात करें तो वर्ष 2016 में देश भर में 17 किसानों ने हर रोज खुदकुशी की, यानी कुल 6,351 किसानों ने खुद की जान ली।

यदि किसी व्यक्ति में मानसिक रोग के लक्षणों की पहचान करने की बात की जाए तो प्रारंभिक रूप में उदासी, भ्रमित सोच, एकाग्रता में कमी, अत्यधिक डर या चिंता, अत्यधिक अपराधबोध की भावना, आत्महत्या की भावना, याद्दाश्त में कमी जैसे लक्षण मानसिक रोग होने की पुष्टि करते हैं। यह वर्तमान में आम हो चला है, क्योंकि कार्य का दबाव, परिवार का दबाव, जिम्मेदारियों का दबाव इत्यादि वह स्थितियां हैं जिनमें व्यक्ति खुद को तनाव रहित रख पाने में असमर्थ होते जा रहा है।

हमारी आबादी बढ़ते हुए सवा सौ करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है, लेकिन इतनी आबादी पर सिर्फ सात लाख चिकित्सक ही हैं। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो यह स्थिति और भी विकट है, क्योंकि देश में केवल पांच हजार मनोचिकित्सक हैं और दो हजार से कम क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक हैं। आशा है कि इस स्थिति में जल्द सुधार होगा।

(लेखक देवी अहिल्या विवि में अध्येता हैं)

मेलबाक्स

संबंधों के होते हैं कई आयाम

खुद लड़नी होगी अपनी लड़ाई शीर्षक से लिखे अपने लेख में ब्रह्मा चेलानी ने कहा है कि पाकिस्तानी आतंकवाद से निपटने में अमेरिका सहित कोई भी मित्र देश उतना मददगार नहीं होगा। यह भारत की लड़ाई है जो उसे खुद ही जीतनी होगी। इस लेख के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रों की आत्महित-चेतना ही स्थायी विचार होता है, शत्रु-मैत्री संबंध उसी के द्वारा संचालित होते हैं। पाकिस्तान और चीन से निपटने में भारत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जितना उपयोग कर सकता है, उतना कर रहा है। उसी प्रकार अमेरिका चीन-पाक के संदर्भ में भारत का प्रयोग करता है। सबसे बड़ी राहत जो ट्रंप के कारण हमें मिली है, वह चीन को लेकर है। पाक आतंक से भारत स्वयं निपट सकता है, यह वस्तु-स्थिति है, किंतु चीन का डंक दबाने में ट्रंप की नीतियां भारत के हितों के लिए बेहद मुफीद रहीं, इस तथ्य की ओर लेखक का ध्यान गया प्रतीत नहीं होता। दोस्ती का मतलब यह नहीं हो सकता कि ट्रंप हर बात पर मोदी की हां में हां मिलाएं। आखिर भारत भी कब ऐसा करता है? रूस के साथ एस-400 सौदा अमेरिकी विरोध के बावजूद हमने परवान चढ़ाया। चीन के साथ हमारे ताल्लुक हमारे अपने हितों द्वारा निर्देशित हैं, यद्यपि अमेरिकी झटकों के कारण चीन अब हमें अधिक महत्व देने लगा है। यूं तो भारत ने जो सैन्य शक्ति हासिल कर ली है, उसकी वजह से विश्व की बड़ी ताकतें भी हमारा सम्मान करने के लिए बाध्य हो रही हैं, पाक की तो हैसियत ही क्या।

अजय मित्तल, मेरठ

देसी गाय का गोबर

रामसरण वर्मा का लेख, कृषि संकट के कारण समझें किसान, पढ़ा। वह लिखते हैं कि गोबर की खाद से 20 प्रतिशत तक उत्पादन बढ़ सकता है। यहां उनके कथन में संशोधन करना चाहूंगा। कायदे में किसी भी पशु का नहीं, बल्कि यह गोबर देसी गाय का ही होना चाहिए। पद्मश्री कृषि वैज्ञानिक सुभाष पालेकर ने प्रयोगों के द्वारा सिद्ध कर दिखा दिया है कि केवल एक देसी गाय 30 एकड़ तक भूमि के लिए पर्याप्त खाद दे सकती है। उनके प्रयोग जहां-जहां दोहराए गए, एक से एक उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए हैं। उप्र में लखनऊ के निकट मलीहाबाद आम का मशहूर इलाका है। यहां कृषकों ने आम्र वृक्षों के बीच हल्दी बोई। इसके लिए एनडी-2 बीज लिया। देसी गाय का गोबर डाला और फसल जबरदस्त हुई। आम से भी ज्यादा कमाई हल्दी से हो गई। इसके अलावा मशरूम तथा विदेशी सब्जियों में ब्रोकली, लिटस और पाकचोई बोकर भी देसी गोबर के कारण अत्यधिक मुनाफा हुआ है। किसी भी पशु का गोबर कुछ समय के लिए अच्छे परिणाम दिखा सकता है, किंतु लंबे समय के लिए देसी गाय का ही गोबर चाहिए। बिहार के नालंदा, उप्र के शामली और कानपूर देहात तथा हरियाणा में देसी गाय ने किसानों की तकदीर बदल दी है। विदेशी नस्ल की गायों की अपेक्षा इनका गोबर उठाने में भी सुविधाजनक होता है। इसमें दुर्गंध भी नहीं होती है। इन गायों का दूध भी मीठा होता है। लेख में सभी पहलुओं को शामिल करना चाहिए। जिससे किसानों को सही जानकारी मिल सके।

mittalmrtw@gmail.com

मधुमक्खी से सीखें

दैनिक जागरण के 6 अक्टूबर के अंक में संपादकीय, विकास और पर्यावरण, दोनों के बीच संतुलन कायम करने पर जोर देता है। यह सत्य है कि हमारे लिए विकास भी उतना ही जरूरी है, जितना पर्यावरण। लेकिन जब विकास के लिए पर्यावरण की हानि होती है तो दर्द होता है, लेकिन यही दर्द तब भी होता है जब विकास नहीं होता है। चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकारें उन सबको प्रकृति के जीव मधुमक्खी से सबक लेना होगा। मधुमक्खी को शहद का निर्माण करने में प्रकृति प्रदत फूलों, पेड़, पौधों और पत्तियों की भी जरूरत होती है। वह फूलों, पत्तियों से शहद निर्माण के आवश्यक तत्व रस लेती है और शहद बनाती है। इस प्रक्रिया में मधुमक्खी पर्यावरण को कतई नुकसान नहीं पहुंचाती है। संपादकीय में भी यही इशारा किया गया है। मधुमक्खी की तरह संतुलन कायम कर हम विकास करने के साथ, पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। पर्यावरण को बचाना इसलिए सबसे जरूरी है, क्योंकि मानव जीवन का अस्तित्व इसी पर निर्भर है।

hemahariupadhyay@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्